प्रेषक.

राम सिंह, प्रमुख सचिव एवं विधि परामर्शी, उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में.

जिलाधिकारी, नैनीताल।

न्याय अनुभाग-1

देहरादून : दिनांक : 28 अक्टूबर, 2015

विषयः श्री ललित मोहन तिवारी, उप जिला शासकीय अधिवक्ता (सिविल), रामनगर, जिला नैनीताल का कार्यकाल बढाया जाना।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या—572 / चौहद / राजस्व सहायक / 2015—16 दिनांक 07.09.2015 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

- 2— इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री लिलत मोहन तिवारी, उप जिला शासकीय अधिवक्ता (सिविल), रामनगर, जिला नैनीताल का कार्यकाल दिनांक 14.09.2015 से अग्रेत्तर 05 वर्ष अर्थात दिनांक 13.09.2020 तक बढाये जाने की महामिहम राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। 3— उक्त स्वीकृति इस शर्त के अधीन की जाती है कि यह एक व्यवसायिक आबन्धन है। किसी सिविल पद पर नियुक्ति नहीं है। राज्य सरकार किसी भी समय बिना कोई कारण बताये एवं बिना किसी पूर्व सूचना के उप जिला शासकीय अधिवक्ता (सिविल), रामनगर, जिला नैनीताल के पद पर श्री लिलत मोहन तिवारी की आबद्धता समाप्त कर सकती है अथवा श्री तिवारी भी इस आबद्धता को किसी भी समय समाप्त कर सकते है। श्री तिवारी, इस आशय का सहमित प्रमाण पत्र भी जिला मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत करेंगे
- 4— कृपया तद्नुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राम सिंह) प्रमुख सचिव

14-alt-L()

संख्या- /XXXVI(1)/2015—17 चार—एल0 / 03 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :- '

1- जिला न्यायाधीश, नैनीताल।

2-- वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल।

3- निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।

कि उन्हें इस शर्त पर कोई आपत्ति नहीं है।

4- सम्बन्धित अधिवक्ता।

5-- गार्ड फाईल/एन०आई०सी०।

(महेश चन्द्र कौशिवा) अपर सचिव

C:\Users\lenovo\Documents\Bhagwan folder\Dgc apointment\dgc letter.doc